पाकिस्तान ने नज़र उठाने की कोशिश की तो, जो अब तक नहीं हुआ वह होकर रहेगा- राजनाथ

राव दूदाजी मूर्ति अनावरण पर रक्षा मंत्री ने कहा, भजनलाल शर्मा का नाम सफल व कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाएगा

नागौर/जयपुर, 14 मई। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश की सुरक्षा नीति में व्यापक और ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर पाकिस्तान ने नजर उठाने की कोशिश की, तो जो अब तक नहीं हुआ, वह होकर रहेगा।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राव दूदाजी ने वीरता व स्वाभिमान की ऐसी परम्परा स्थापित की, जिसने राजस्थान को गौरवान्वित किया। उन्हीं के वंश में मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्त हुई, जिनकी वाणी सदियों बाद भी भक्ति और मानवता का संदेश दे रही है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में श्री राव दूदाजी के मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल हुए।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में श्री राव दूदाजी के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2023 में चुनाव के बाद पर्यवेक्षक के रूप में मैं यहां आया था और विधायक दल ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। उसके बाद राजस्थान प्रगति के हर मापदंड को तेजी से पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भजनलाल शर्मा का नाम सफल और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राव दूदा जैसे वीर शिरोमणि का जीवन नई पीढ़ी के लिए आदर्श है। राव दूदा का अर्थ है, संकल्प, समर्पण, शक्ति और शौर्य। अश्व पर सवार दूदा जी की प्रतिमा हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का संदेश देती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अस्मिता और मातृभूमि की रक्षा के लिए राजस्थान के वीर किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते हैं। राव दूदाजी ने वीरता-स्वाभिमान की ऐसी परम्परा स्थापित की है, जिसने पूरे राजस्थान को विश्वभर में गौरवान्वित किया है। साथ ही, उन्हीं के वंश में मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्त भी हुईं। मीरा की वाणी कालजयी हैं। सदियों बाद भी उनकी वाणी भक्ति और मानवता का सन्देश दे रही है।

केन्द्रीय कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने अद्भुत क्षमता का परिचय देते हुए आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर भारत के प्रत्येक नागरिक का मस्तक गर्व से ऊंचा करने का काम किया।

इस दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने मीरा बाई के पेनोरमा का अवलोकन भी किया। इससे पहले उन्होंने श्री राव दूदा मेड़तिया जी की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने श्री चारभुजा नाथ एवं मीराबाई मंदिर में दर्शन किए एवं देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ मंजू बाघमार, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत और लक्ष्मण राम, पूर्व राज्यसभा सांसद गज सिंह सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मूर्ति अनावरण आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एस्कॉर्ट छोड़ी

जयपुर, 14 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से ऊर्जा संरक्षण को लेकर देशवासियों से किये गये आ ान के बाद, राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने वाहन के साथ चलने वाली

- उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा रोडवेज़ बस से फागी पहुँचे।

एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। एसीजे शर्मा अब अपने वाहन से बिना पायलट गाड़ी के आवाजाही कर रहे हैं। इसी तरह निचली अदालतों के भी कई मजिस्ट्रेट कार पूलिंग कर अदालतों में पहुंच रहे हैं।

गौरतलब है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से आ ान किया था कि वे ऊर्जा और खाद्य तेल का कम से कम उपयोग करें। इसके बाद उन्होंने अपने काफिले के वाहनों की संख्या भी काफी सीमित कर दी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने साथ चलने वाले वाहनों के बेड़े को हल्का किया। इसी तरह डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आज रोडवेज बस के जरिए फागी पहुंचे।

चुनाव आयुक्त के चयन में स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं- सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा, चयन समिति में विपक्ष के नेता की भूमिका प्रतिकात्मक, क्योंकि निर्णय 2:1 के अनुपात से पहले ही तय

- सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि केवल स्वतंत्रता का दावा पर्याप्त नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता वास्तविक और स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

नई दिल्ली, 14 मई। देश में चुनाव आयोग के शीर्ष पदों, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के कानून पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि मौजूदा चयन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रभाव इतना अधिक दिखाई देता है कि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है।

यह टिप्पणी उस समय आई, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति प्रक्रिया तय की गई है। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और मामले की अगली तारीख पर आगे विचार किया जाएगा।

वर्तमान कानून के अनुसार, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसी संरचना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें किसी भी स्वतंत्र सदस्य को शामिल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि इस व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया लगभग तय हो जाती है, क्योंकि दो सदस्य सरकार से जुड़े होते हैं और तीसरे सदस्य का प्रभाव सीमित रह जाता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि चयन समिति में विपक्ष के नेता की भूमिका केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाती है। कोर्ट ने सवाल किया कि यदि अंतिम निर्णय 2:1 के अनुपात में पहले से ही तय है, तो इस समिति में संतुलन का दावा कितना वास्तविक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी कैबिनेट मंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ जाएगा।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि केवल स्वतंत्रता का दावा पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता वास्तविक और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देनी चाहिए। कोर्ट ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और इसके लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता अनिवार्य है।

सुनवाई के दौरान इस मामले को संविधान पीठ (पांच जजों की बड़ी बेंच) को भेजने पर भी विचार हुआ, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और 324 की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है। हालांकि, इस पर सभी पक्षों में सहमति नहीं बन सकी और सुनवाई को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया।

आयात बिल घटाने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोयले (जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है) को गैस, रसायन और ईंधन में बदल दिया जाए, जिन्हें भारत वर्तमान में उच्च लागत पर आयात करता है।

नाम के विपरीत, कोल गैसीकरण में कोयले को जलाया नहीं जाता। इसमें क्रश किए गए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ बहुत उच्च तापमान और दबाव में गर्म किया जाता है।

असल में, कोयला आयातित प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक का मजबूत विकल्प बन जाता है।

भारत का एलएनजी, मेथनॉल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य प्रतिस्थापन योग्य उत्पादों के लिए आयात बिल वित्त वर्ष 25 में 2.77 लाख करोड़ रुपये था। कोल गैसीकरण इस बिल को सीधे प्रभावित करता है।

उल्लेखनीय है कि 2024 में, कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भारत का पहला भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, ताकि ऐसे भंडार का लाभ उठाया जा सके। यह परियोजना इसलिए भी आशाजनक है, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर कोयले मिलता है।

भारत 2030 तक 100 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला गैसीकरण हासिल करना चाहता है। यह पहले उठाए गए कदमों पर आधारित है:

2018: तालचर कोयला गैसीकरण-आधारित उर्वरक घोषणा, 2020: व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी में प्रोत्साहन, 2021: कोयला आधारित हाइड्रोजन का रोडमैप, जनवरी 2024: 8 परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये का समर्थन, और मई 2026: नई 37,500 करोड़ रुपये की विस्तार योजना।

असम पुलिस ने दूसरे दिन भी पवन खेड़ा से 8 घंटे पूछताछ की

- खेड़ा को 25 मई को फिर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

गुवाहाटी, 14 मई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा गुरुवार को लगातार दूसरे दिन असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुए। यह पूछताछ असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा से जुड़े कथित बहु-विदेशी पासपोर्ट मामले को लेकर चल रही जांच के संबंध में की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को पवन खेड़ा से करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई। हालांकि, क्राइम ब्रांच कार्यालय में प्रवेश करते समय और बाहर निकलने के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वे अब भी अपने पुराने आरोपों और बयानों पर कायम हैं, तब भी उन्होंने चुप्पी बनाए रखी। जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को आगे की पूछताछ के लिए 25 मई को फिर से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले बुधवार को भी उनसे लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद देर रात उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, "दिल्ली में एक और निर्भया मामला! लड़कियां स्कूल में सुरक्षित नहीं, बसों में सुरक्षित नहीं।" यह घटना 2012 के दिल्ली बस गैंगरेप मामले की याद दिलाती है, जिसमें 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा (बाद में निर्भया के नाम से जानी गई) को दक्षिण दिल्ली की एक चलती बस में छह पुरुषों ने बेरहमी से पीटा, दुष्कर्म किया और फिर गंभीर रूप से घायल स्थिति में सड़क पर फेंक दिया। गंभीर चोटों के चलते 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिज़ाबेथ अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी।

20 साल बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने बताया कि इस मामले में मुख्य व प्रथम गवाह और शिकायतकर्ता गृह विभाग में एक वरिष्ठ अफसर है। परंतु हैरानी की बात है कि उनके द्वारा दर्ज एफआईआर में जांच अधिकारी बिना आदेश के बदल दिया गया। एफआईआर को एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया और लगभग 20 वर्ष तक कोई जांच नहीं की गई परंतु आरोपियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया।

वकील ममता ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा

हाईकोर्ट ने 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा के मामले में सुनवाई की

कोलकाता, 14 मई। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं और 2021 के विधानसभा चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रखा। वे सुबह वकील के परिधान में उच्च न्यायालय परिसर पहुंचीं और मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं।

ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि वे पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 में बार काउंसिल में उनका पंजीकरण हुआ था और तब से वे सदस्यता का नवीनीकरण कराती रही हैं।

अदालत में ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद राज्य में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विवाहित महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां दी जा रही हैं, घरों में लूटपाट और आगजनी हो रही है तथा पुलिस कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अनुमति मिलने पर इन शिकायतों को अतिरिक्त हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करेंगी और राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर राज्य नहीं है, यह पश्चिम बंगाल है। कृपया राज्यवासियों को बचाइए।

- ममता बनर्जी ने कहा कि उनका 1985 में बार काउंसिल में पंजीकरण हुआ था और वे तब से सदस्यता का नवीनीकरण कराती रही हैं। हालांकि वे पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट में बहस कर रही हैं।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता धीराज त्रिवेदी ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने अदालत में कहा कि याचिका में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि किस स्थान पर क्या घटना हुई। ?

उनका कहना था कि राज्य पुलिस सतर्क और सक्रिय है तथा जिन 2000 से अधिक शिकायतों का उल्लेख किया जा रहा है, उनके समर्थन में कोई ठोस विवरण नहीं दिया गया है।

होर्मुज़ के पास गुजरात के एक और जहाज़ पर हमला

नई दिल्ली, 14 मई। मिडिल ईस्ट में जारी तनातनी के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट से सटे ओमान तट पर गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, इसी दौरान उस पर ड्रोन या मिसाइल जैसे हथियार से हमला किया गया, हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि, ओमान कोस्टगार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। भारत ने बुधवार को ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ष

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

16 राज्यों व 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में होगी एसआईआर

चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया

नई दिल्ली, 14 मई। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने से जुड़ी प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का निर्देश जारी कर दिया है। एसआईआर के पहले दो चरणों में 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश कवर होगा।

- एसआईआर के इस तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़ कर पूरा देश कवर किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश (4,16,16,061), अरुणाचल प्रदेश (8,87,607), चंडीगढ़ (5,18,663), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (4,27,849), हरियाणा (2,06,63,155), झारखंड (2,64,89,777 मतदाता), कर्नाटक (5,55,74,064), महाराष्ट्र (9,86,64,413), मणिपुर (20,91,999), मेघालय (23,43,252), मिजोरम (8,75,004), नागालैंड (13,56,858), दिल्ली (1,48,23,234), ओडिशा (3,34,33,659), पंजाब (2,14,56,297), सिक्किम (4,71,094), त्रिपुरा (28,97,674), तेलंगाना (3,39,20,705) और उत्तराखंड (79,76,466) शामिल हैं।

मतदाता सूची अपडेट करने के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे। इसमें उनकी सहायता 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) करेंगे। बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से गणना चरण के दौरान नियुक्त किये जाते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बीएलए नियुक्त करें।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक संदेश में कहा, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपने गणना फॉर्म भरें। आयोजन का उद्देश्य मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं को ही शामिल करना और अपात्र व्यक्ति का हटाना है।

सतीशन मु.मंत्री बने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की कि उनके पास राज्य के विधायकों का समर्थन है और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

लेकिन सभी तरफ से दबाव के बाद, राहुल गांधी ने सुरक्षित विकल्प अपनाया और सतीशन को मुख्यमंत्री चुन लिया।

इस प्रक्रिया में पार्टी के वफादार और मूल्यवान सदस्य रमेश चेन्निथला नाराज़ और दुखी हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र चले गए और किसी से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि 2011 में जब उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई थी, तो उन्हें ओमन चांडी को रास्ता देने को कहा गया, क्योंकि वे वरिष्ठ थे। और अब उन्हें बताया जा रहा है कि वे बहुत वरिष्ठ हैं और युवा नेताओं को अवसर दिया जाना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने के.सी. वेणुगोपाल को लॉलीपॉप ऑफर की है कि वे एआईसीसी में काम करते रहें और 10 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, उसमें उन्हें अवसर मिलेगा। राहुल गांधी वादे करने के लिए जाने जाते है, पर उनके अधिकांश वादे पूरे नहीं होते।

ऐसा ही सचिन पायलट के साथ हुआ था। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस की जीत होने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। लेकिन बाद में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन को उपमुख्यमंत्री पद ऑफर किया गया। यदि सचिन ने इसे स्वीकार न किया होता, तो राहुल गांधी और नेतृत्व पर दबाव पड़ सकता था और खेल अलग दिशा में जा सकता था।

- केरल के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने भी राहुल को केरल की जनभावना को स्वीकार करने की सलाह दी। पर, सबसे ज्यादा प्रभाव राहुल पर आईयूएमएल के दबाव का पड़ा, क्योंकि आईयूएमएल की राहुल के पुराने चुनाव क्षेत्र वायनाड में निर्णायक भूमिका ही नहीं है, बल्कि उसके 22 विधायकों के संख्या बल का भी दबाव है। साथ ही आईयूएमएल कई और सीटों पर भी कांग्रेस को जीतने में मदद करती है।

ठीक उसी तरह, सतीशन अपनी मांगों और हक के लिए दृढ़ता से खड़े रहे और उन्होंने बाजी पलट दी।

यह प्रकरण कांग्रेस नेताओं के लिए सबक है कि खेल को समझदारी और रणनीति से कैसे खेला जाए।

हद है चाकरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के प्रिय हैं, और वे वेणुगोपाल द्वारा निशाना बनाए जाने से बचना चाहते हैं।

जिन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने भी केसी वेणुगोपाल के कांग्रेस पार्टी के प्रति महान निष्ठा, बलिदान और समर्पण की तारीफ में लिखा है।

हरीश चौधरी ने केवल एक शब्द लिखा: "स्टेट्समैन"

एआईसीसी में अधिकांश कांग्रेस नेता सतर्कता बरत रहे हैं।

सिर्फ सचिन पायलट हैं, जिन्होंने केरल के मुख्यमंत्री बनने पर वी. डी. सतीशन को बधाई दी है।

अन्य सभी वेणुगोपाल समर्थक मौन हैं, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्ता रेड्डी, अजय माकन, मुकुल वासनिक और कई अन्य शामिल हैं।

यह संभवत: कांग्रेस पार्टी के पतन की नई पराकाष्ठा है।

शी-ट्रंप वार्ता कोई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुकी है। ट्रम्प का दृष्टिकोण अधिक लेन-देन और शुल्क-केन्द्रित है, जबकि शी का चीन रणनीतिक आत्मनिर्भरता और पश्चिम पर निर्भरता कम करने पर केन्द्रित है। जब वे सहयोग की बात करते हैं, तब भी दोनों टैक्नॉलजी, ट्रेड, सैमिकंडक्टर, ए.आई., रेयर अर्थ्स और इंडो-पैसिफिक में सैन्य प्रभाव की एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं।

तीसरा, यह बैठक जितनी भू-राजनीति के बारे में है, उतनी ही घरेलू राजनीति से भी जुड़ी है। ट्रम्प चीन के प्रति कठोरता दिखाते हैं, क्योंकि यह अमेरिका के औद्योगिक और राष्ट्रवादी मतदाताओं में लोकप्रिय है। वहीं शी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या जनता के सामने कमजोर नहीं दिख सकते। इसलिए दोनों नेता कम कॉम्प्रोमाइज़ के साथ नैगोसिएशन में उतरते हैं। यही कारण है कि ऐसी बैठकें अक्सर स्थायी समझौते के बजाय, केवल माहौल और टैम्परेरी अण्डरस्टैण्डिंग पैदा करती हैं।

भारत के लिए, इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। जब अमेरिका-चीन तनाव नियंत्रित रहते हैं तो भारत को लाभ होता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरी तरह से अनबन, वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतों, इन्वैस्टमैंट फ्लो और निर्यात बाजारों को नुकसान पहुँचाएगी। साथ ही, अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती दूरी से भारत को रणनीतिक रूप से भी लाभ हो रहा है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और पश्चिमी सरकारें भारत को एक वैकल्पिक मैनुफैक्चरिंग, भू-राजनीतिक और तकनीकी पार्टनर के रूप में देख रही हैं।

लेकिन नई दिल्ली के सामने एक नाजुक संतुलन की चुनौती भी है। वह न तो वॉशिंगटन और न ही बीजिंग पर अत्यधिक निर्भर हो सकती है। भारत की वर्तमान रणनीति सोची समझी मल्टी अलाइनमैंट वाली लगती है: अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध गहरे करना, साथ ही चीन के साथ इतना जुड़ाव बनाए रखना कि खुले तौर पर टकराव से बचा जा सके।

सारांश यह है कि ट्रम्प-शी की बैठक एक नई वैश्विक सच्चाई को उजागर करती है: अमेरिकी प्रभुत्व और कोऑपरेटिव ग्लोबलाइज़ेशन का युग समाप्त हो गया है। उभरता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर, बाइपोलर, लेन-देन वाला, आर्थिक रुप से बंटा हुआ और स्ट्रैटेजिक रुप से संदिग्ध होता जा रहा है। मीटिंग से कुछ समय के लिए माहौल की गर्मी और तनाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन इससे इतिहास की मूल दिशा नहीं बदलती।

यूपी में आँधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में घायल व्यक्ति की पहचान नन्हे मियां के रूप में हुई। जमीन पर गिरने के बाद उन्हें चोटें आईं, उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गए। यह घटना बरेली जिले के भामोरा थाना क्षेत्र के बमियाना गांव में हुई। नन्हे मियाँ ने एनडीटीवी को बताया, "मैं 30-40 फीट ऊँचाई तक उड़ गया था। मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा। मैं कम से कम 50 फीट दूर गिरा था। उन्होंने बताया कि वे रस्सी पकड़े हुये थे तथा उन्हें उम्मीद थी कि यह उन्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन तेज हवा ने रस्सी तोड़ दी। एक अधिकारी, जो चिकित्सा व्यवस्था के दौरान मौजूद थे, ने नन्हे मियां से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि तूफान, बारिश और बिजली से हुए नुकसान की जानकारी हर तीन घंटे में अपडेट करें। गुरुवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि राहत उपायों, जिनमें मुआवजा वितरण भी शामिल है, को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाए। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को पूरे राज्य में हुई बारिश और तूफान में कम से कम 89 लोग मारे गए, 53 घायल हुए, 87 घर क्षतिग्रस्त हुए तथा 114 पशु भी मारे गए। प्रयागराज, भदोही, फतेहपुर और सोनभद्र जिलों से भारी तबाही की खबरें आई हैं।

एयर इंडिया फ्लाइट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि यह भोजन भारतीय संस्कृति में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि अधिकांश लोग इसे मंदिर के प्रसाद, उत्सवों के दौरान सुबह के भोजन, रविवार के नाश्ते या सड़क किनारे के भंडारों से जोड़ते हैं, न कि एयरलाइन की ट्रे टेबल से। प्रीति जैन ने इस पल को एक्स पर साझा किया, जिसने तुरंत ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा: "मेरे परिवार में और शायद मेरे पूरे दोस्तों में यह पहला मौका है कि उड़ान में हलवा पूरी चना परोसा गया। यह हमारी दिल्ली से बाली की उड़ान पर हुआ। मेरे पति यह देखकर हैरान थे, उन्होंने इसे नहीं खाया, क्योंकि उन्हें ठंडी पूड़ी ज्यादा पसंद नहीं हैं। मैं (इस भोजन को पाकर) बहुत खुश थी और मैंने उनके भोजन को भी खा लिया। मज़ाक में कह रही हूँ कि क्या किसी और को कभी एयर इंडिया की उड़ान में यह परोसा गया है?" यह पोस्ट ऑनलाइन तुरंत वायरल हो गया। और सच कहें, तो यह समझना आसान है। बहुत से भारतीयों के लिए यह भोजन भावनाओं से जुड़ा है। यह उन भोजनों में से है, जो पहली ही बाइट लेने से पहले खुशी का अहसास दिला देते हैं, और यही कारण है कि इसे अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर देखना बेहद अप्रत्याशित लगा। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "(यह भोजन) शायद पास के किसी भंडारे से लिया गया होगा।" एक अन्य यूजर ने इंटरनेट की भावना को सही तरीके से व्यक्त किया, "हलवा पूड़ी चना को इन-फ्लाइट भोजन के रूप में पाना सच में सबसे ज्यादा अप्रत्याशित देसी एयरलाइन अनुभवों में से एक है।" कुछ लोग अपनी उड़ान के खाने के अनुभव याद करके भावुक भी हो गए। एक व्यक्ति ने साझा किया, "एक बार 8-10 दिन के ऑनसाइट काम के बाद लौटते समय, मुझे दाल चावल परोसा गया। यह भोजन आश्चर्यजनक था, मेरी ऐसा ही कुछ खाने की इच्छा भी हो रही थी।" प्रीति ने भी बताया कि उनके पति ने इसे नहीं खाया, क्योंकि उन्हें ठंडी पूड़ी पसंद नहीं हैं, और कई लोग इससे सहमत भी हुए। लेकिन लोगों ने स्वीकार किया कि यह मेनू विकल्प अविस्मरणीय था।

ब्रिक्स देशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सक्रियता तथा इस समूह का रणनीतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने पर केन्द्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस दौरान रूस, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और अन्य ब्रिक्स भागीदार देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्पाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908